भारतीय बैंकों की आस्ति गुणवत्ता : भावी दिशा*

एन.एस.विश्वनाथन

भारतीय बैंक आम तौर पर, एवं सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) विशेषकर, अत्यधिक दबावग्रस्त आस्तियों से जूझ रहे हैं, जो प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में जमा हुई हैं। दबावग्रस्त आस्तियों के विषय में क्यों और क्या को लेकर चाहे कितनी भी चर्चा की जाए कदापि पर्याप्त नहीं होगी, यदि हम इससे यह समझ पाते कि अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की उल्लेखनीय वृद्धि का क्या कारण रहा होगा और यह निश्चित कर पाते कि इसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए, तथा यह पता लगा पाते कि भविष्य में क्या भिन्न किया जा सकता है। इसलिए मैं इस प्रासंगिक मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए एसोचम की सराहना करता हूं और इस विषय पर मुझे अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। मेरी केवल यह आशा है कि इस सम्मेलन से हमारे सामने उपस्थित समस्या के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन होगा और उससे निपटने का उपाय निकलेगा। मुझे लगता है कि यह मुद्दा जटिल है और यकीन है कि हम ऐसे समाधान के साथ यहां से जाएंगे जो रातभर काम करेगा।

आस्ति गुणवत्ता

सकल एनपीए और कुल दबावग्रस्त आस्तियां

भले ही आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं इस मुद्दे को समस्या के आकार और आयाम के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता हूं (चार्ट 1 और 2)। मार्च 2016 के अंत में भारत के वाणिज्यिक बैंकों की कुल दबावग्रस्त आस्तियां बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गईं जिसमें सरकारी क्षेत्र

चार्ट 1: सकल एनपीए (प्रतिशत) का उद्भव

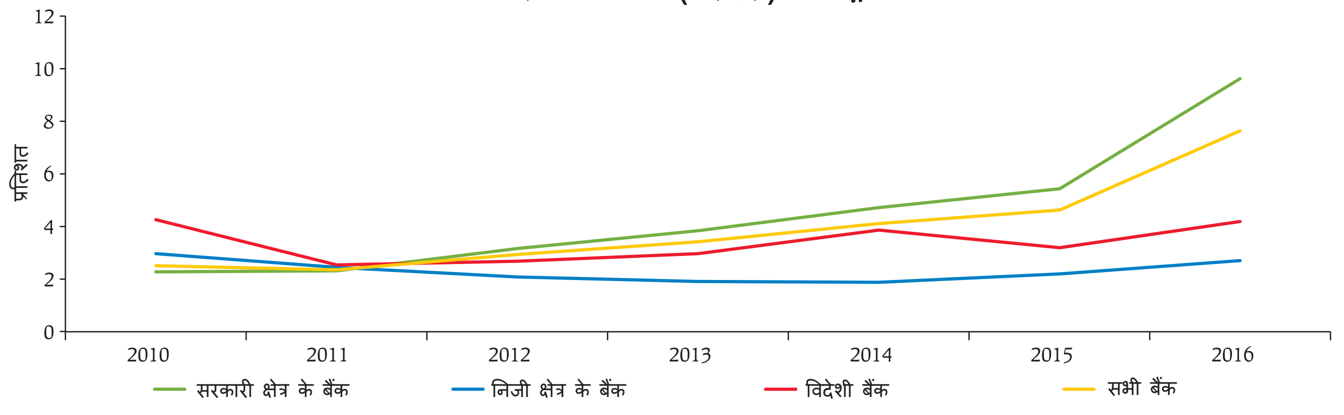

चार्ट 2: दबावग्रस्त आस्तियों (प्रतिशत) का उद्भव

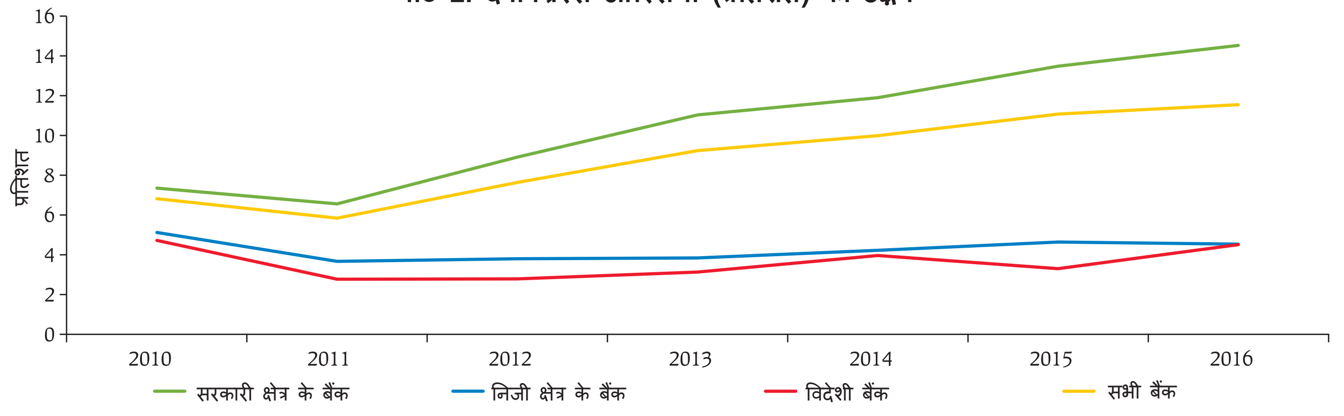

* श्री एन. एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में आयोजित एसोचम के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'जोखिम प्रबंधन : आस्ति गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण' विषय पर कही गई मुख्य बातें। श्री राजीन्दर कुमार, मुख्य महाप्रबंधक के सहयोग के लिए उनका बहुत आभार।

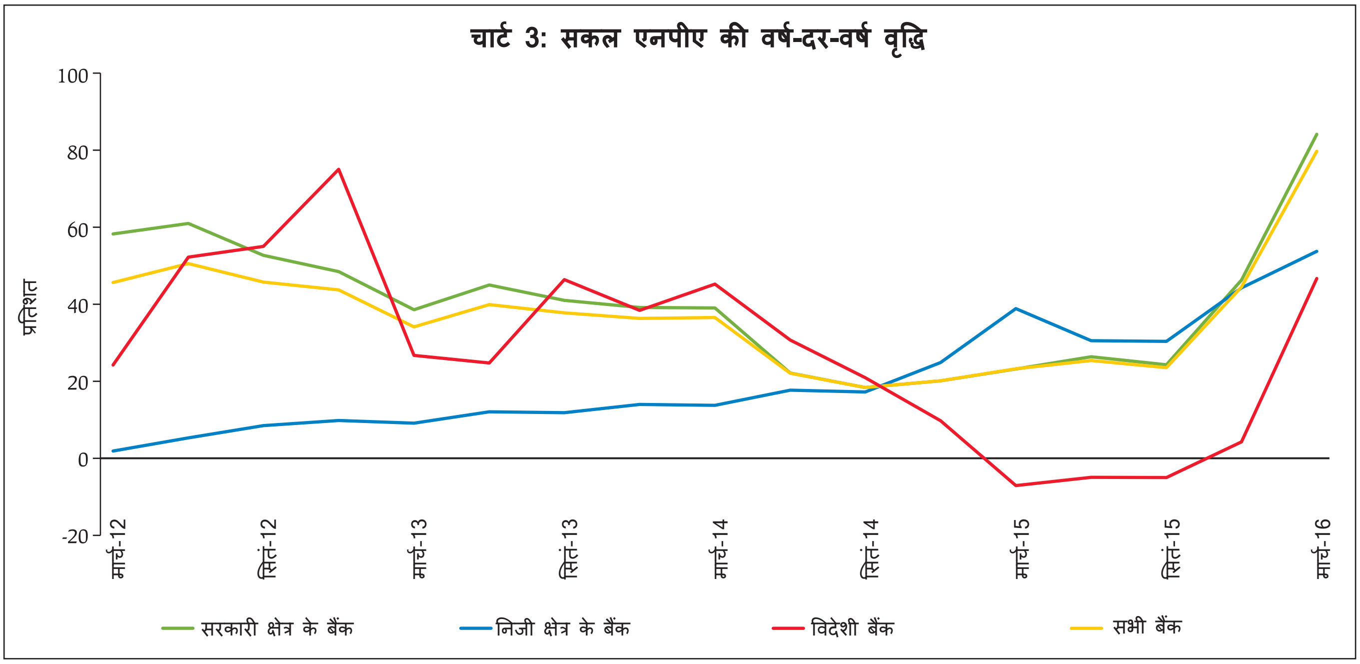

के बैंकों का हिस्सा अधिकतम अर्थात् 14.5 प्रतिशत था। उसमें अभी भी कुछ पुनःसंरचित आस्तियां शामिल हैं जो और अधिक चिंता का विषय बन सकता है, यद्यपि उसकी तीव्रता कम है।

बढ़ता एनपीए

अब हम एनपीए की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि पर नज़र डालते हैं। कोई देख सकता है कि एनपीए में कितनी अधिक वृद्धि हुई है (चार्ट 3)। एक्यूआर प्रयोग के बाद उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि, शायद, भविष्य में एनपीए में वृद्धि घट सकती है लेकिन जैसे जैसे एनपीए पुराना होता जाएगा तत्संबंधी प्रावधान का दबाव लाभ और हानि पर पड़ेगा।

एनपीए का क्षेत्रवार विभाजन

एनपीए के क्षेत्रवार विभाजन एवं कुल दबावग्रस्त आस्तियों पर नज़र डालना भी दिलचस्प होगा (चार्ट 4)। इससे स्पष्टतः उद्योग और बुनियादी संरचना में अत्यधिक दबाव का पता

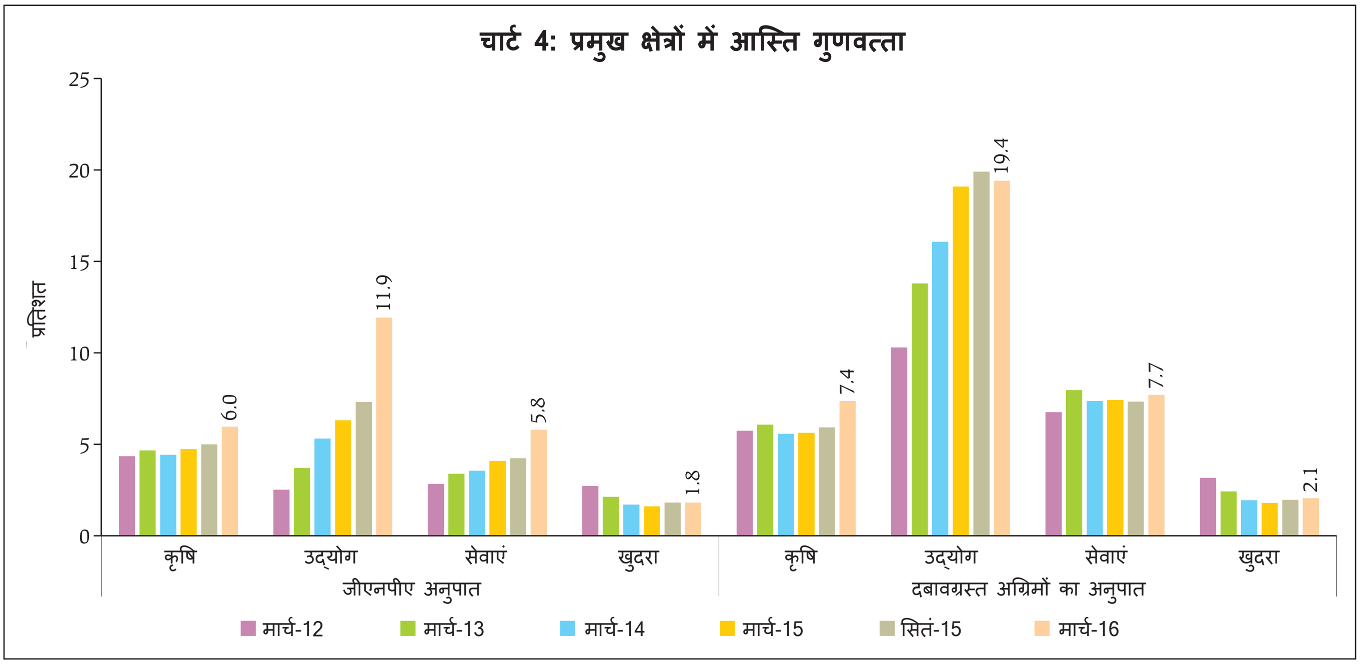

चार्ट 5: मार्च 2016 के अंत में बैंकिंग समूहों में सकल एनपीए का क्षेत्रवार विस्तार

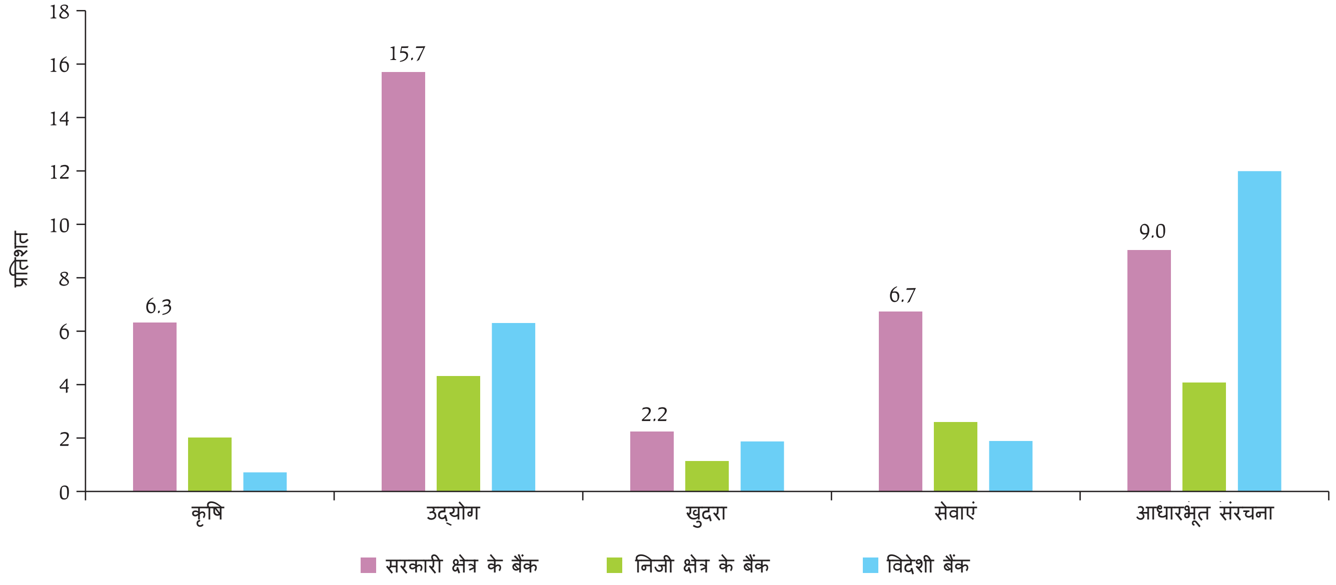

चलता है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में पीएसबी को भारी तनाव का सामना करना पड़ रहा है (चार्ट 5)।

पुनःसंरचित आस्तियां

मार्च 2015 तक पांच वर्षों के दौरान, बैंक कई मामलों में ऋणों के पुनर्गठन से लेकर अनर्जक आस्तियों की पहचान को टालते हुए या जैसा हम अब कहते हैं 'टालते और ढोंग करते हुए' नज़र आए, बजाय इसके कि इकाइयों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में उसका उपयोग करते हुए, जैसा सोचा गया था। परिणामस्वरूप, 2016 तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियां में पुनःसंरचित आस्तियों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो गया, जो ऋण पोर्टफोलियो की खराबी का वास्तविक कारण है (चार्ट 6)।

चार्ट 6: कुल दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पुनःसंरचित आस्तियां

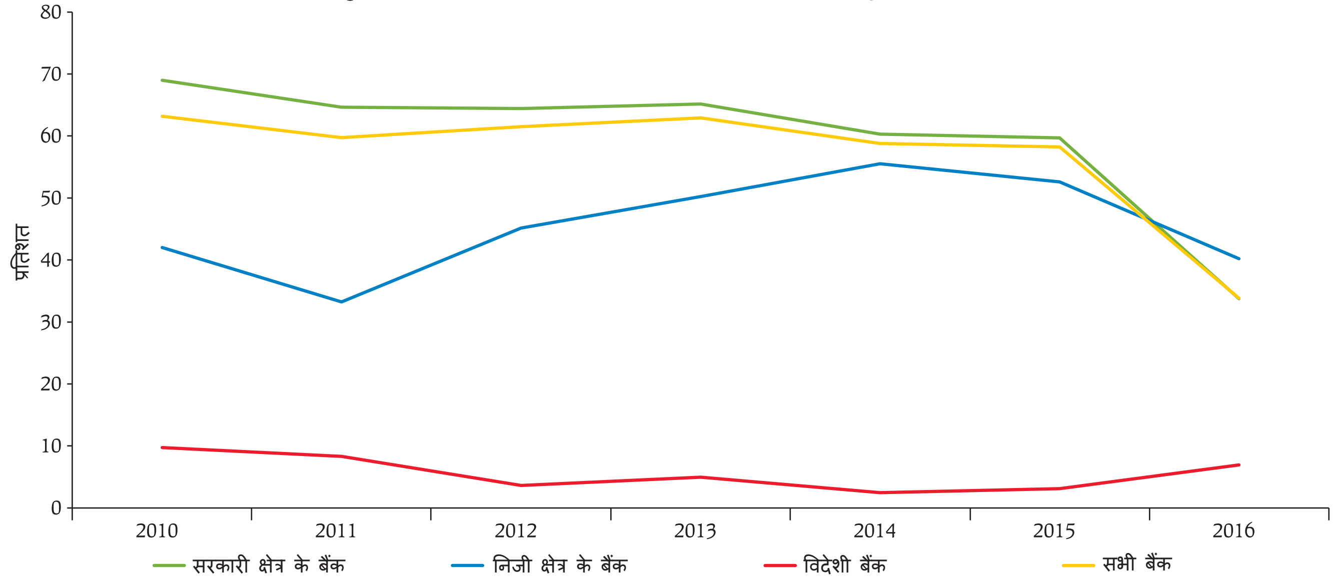

चार्ट 7: निवल एनपीए (प्रतिशत) का उद्भव

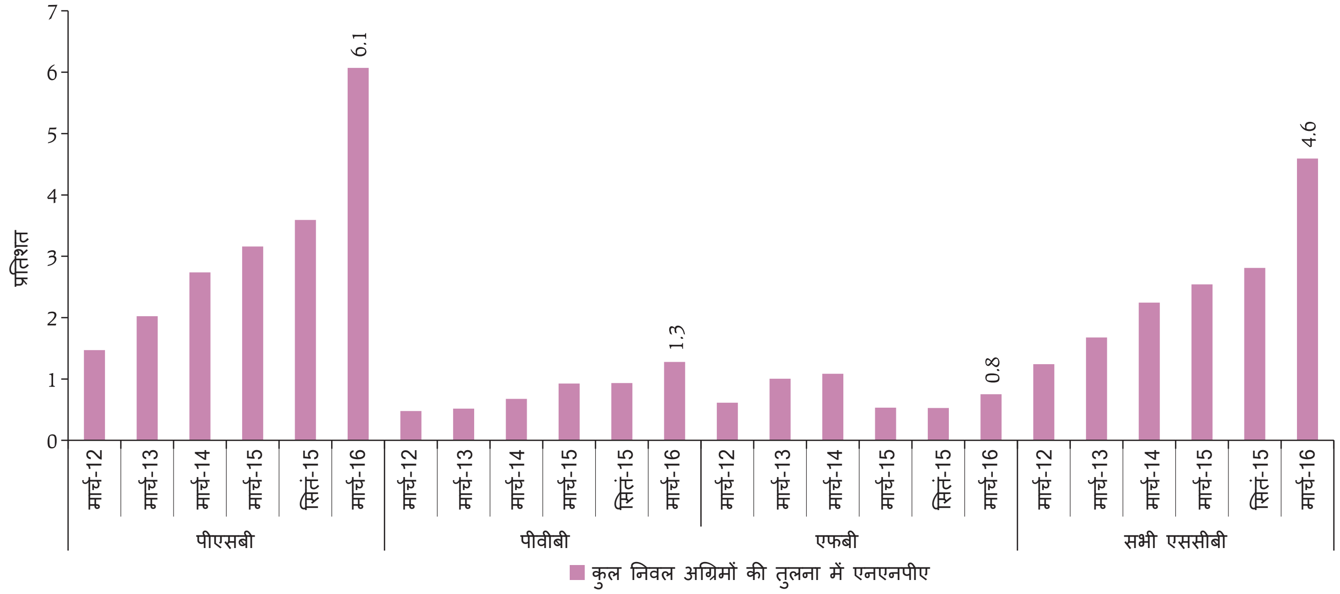

इन वर्षों में, दबाव के बढ़ने के साथ-साथ इन आस्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना पड़ा क्योंकि अलाभकारी इकाइयों के संबंध में किए गए प्रयास निष्फल हुए। चार्ट 6 दर्शाता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इन आस्तियों का अनुपात अत्यधिक था। एक्यूआर के बाद 2016 में इन आस्तियों का बकाया शेष तेजी से घटा, क्योंकि इन आस्तियों के बड़े हिस्से को एक्यूआर के बाद एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जो उसकी वास्तविक गुणवत्ता दर्शाती है (चार्ट 6)।

निवल एनपीए

एनपीए अधिकाधिक मात्रा में होने की वजह से बैंक की आमदनी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप, बैंक की प्रावधानीकरण क्षमता भी दबाव में आई है, जिसके कारण निवल एनपीए का स्तर भी बढ़ा है (चार्ट 7)। उच्च निवल एनपीए निम्न प्रावधान कवरेज अनुपात का संकेत देता है, जो लाभप्रदता में तनाव के कम होने से धीरे-धीरे बेहतर होना चाहिए।

कुछ सहयोगी कारक

एनपीए में वृद्धि की वजह जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। नीचे सारणी 1 और चार्ट 8 से पता चलता है कि बैंक ऋण की वजह से कॉरपोरेट लीवरेज में 2005 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई है। यह ध्यान देने योग्य है कि कॉरपोरेट को 'उच्च लीवरेज' प्राप्त होने के बावजूद, जो कॉरपोरेट ऋण का एक सुस्थापित एवं सर्व ज्ञात जोखिम कारक रहा है, बैंक द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को औसतन 20 प्रतिशत से अधिक की ऊंची दर पर ऋण प्रदान किया जाता रहा है। क्या हम इसे तर्कहीन आधिक्य कहेंगे? स्पष्टतः अत्यधिक लीवरेज युक्त कारोबार अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।

सारणी 1: उच्च ऋण वृद्धि लीडिंग लीवरेज

	06-07	07-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत) (वार्षिक)	9.6	9.3	6.7	8.6	8.9	6.7	5.6	6.6	7.2	7.6(P)
ऋण वृद्धि (प्रतिशत) (वार्षिक - वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार)	28.1	22.3	17.5	16.9	21.5	17.0	14.1	13.9	9.1	10.9
ऋण वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र (प्रतिशत)	26.7	25.0	23.0	24.4	23.6	20.3	15.1	13.1	5.6	2.7

चार्ट 8: इक्विटी की तुलना में ऋण का पूंजी-भारित औसत अनुपात

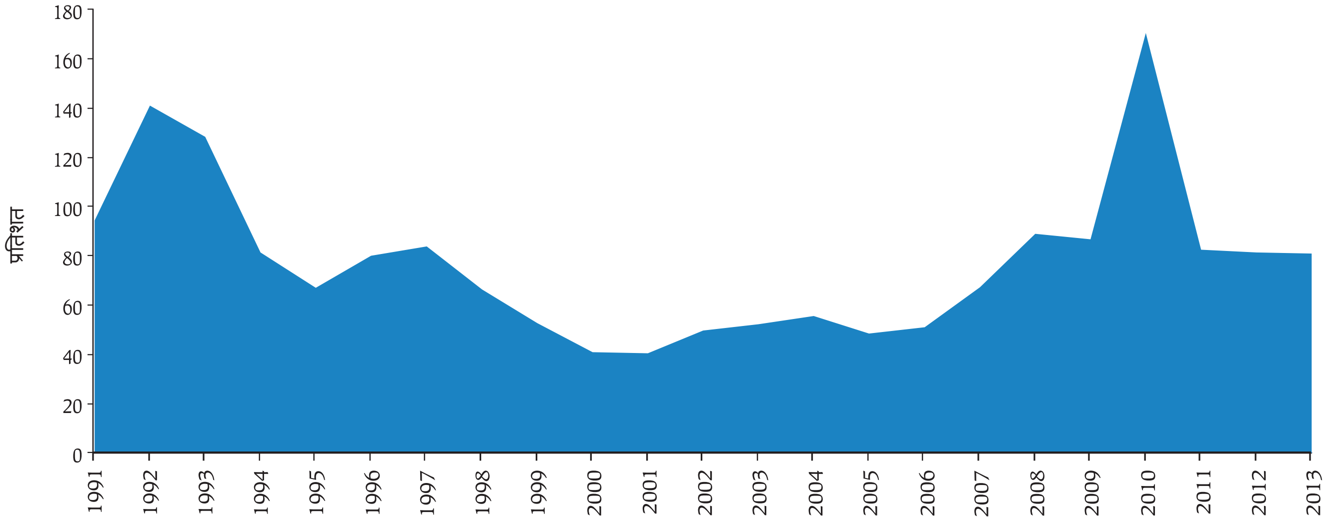

स्रोत : आईएमएफ, कॉरपोरेट अतिसंवेदनशीलता उपयोगिता।

पोर्टफोलियो विविधता विशेष प्रकृति के जोखिम को नियंत्रण में करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों का ऋण पोर्टफोलियो विविधता में, एकल नाम एवं क्षेत्रवार संकेंद्रण दोनों के संदर्भ में, सुधार की गुंजाइश रखता है। चार्ट 9 और 10 बड़े उधारकर्ताओं के खातों में ज्यादा दबाव दर्शाते हैं। संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो में औद्योगिक अग्रिमों का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। यह औद्योगिक क्षेत्र के ऋण के बनिस्बत उच्च तीव्रता के आधार पर आंशिक रूप से न्यायोचित है, लेकिन बैंक को, विशेष रूप से बड़े ऋण वर्ग में, जोखिम और प्रतिलाभ के बीच तालमेल को ध्यान में रखते हुए उचित संतुलन की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए।

चार्ट 9: सकल अग्रिमों और सकल एनपीए में बड़े उधार-कर्ताओं का हिस्सा

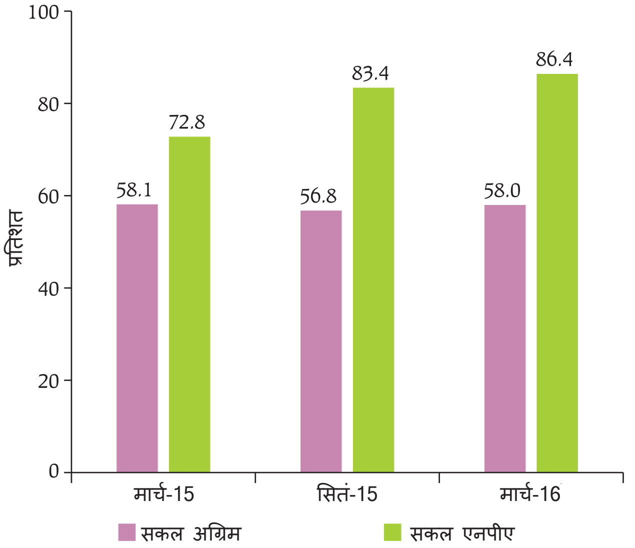

चार्ट 10: बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में प्रतिशत बदलाव

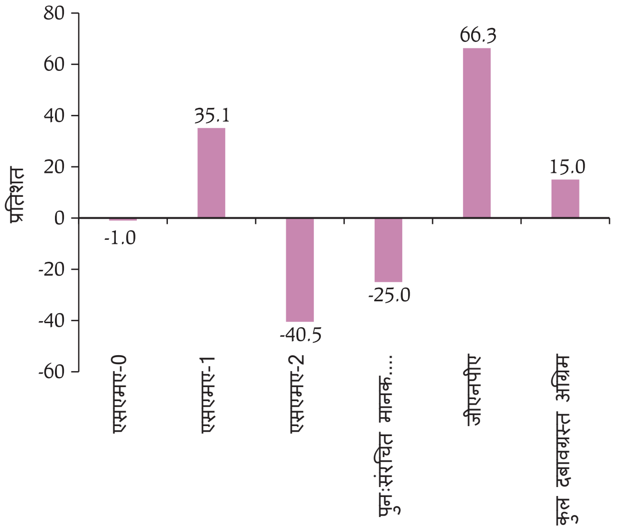

जोखिम प्रबंधन

यह सम्मेलन कम दबावग्रस्त ऋण बही तैयार करने में जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर सही प्रकाश डालता है। इसलिए, चलो मैं उचित ऋण जोखिम प्रबंधन के तत्वों की जांच कर लेता हूं, अतीत को देख लेता हूं और भविष्य के लिए कुछ सबक ले लेता हूं।

बैंक जोखिम उठाने का कारोबार करते हैं। यदि वे जोखिम नहीं उठाते हैं तो वे बैंकिंग कारोबार नहीं कर रहे हैं। लेकिन, जोखिम उठाने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब खतरा उठाना हो सकता है? कब सोच-समझकर लिया गया जोखिम लापरवाही से लिए गए जोखिम से भिन्न होगा?

वास्तव में, जोखिम प्रबंधन में, जोखिम को जानना, उसका आकलन करना और जोखिम की गंभीरता को कम करने के लिए समुचित उपाय करते हुए बैंक की जोखिम-वहन क्षमता की सीमा के अंदर उसे नियंत्रित करना शामिल होगा। चलो हम ऋण जोखिम के विभिन्न स्रोतों की पहचान करते हैं।

ऋण प्रबंधन से होने वाला पहला जोखिम, अनुमान के अनुसार, कारोबार नहीं कर पाने की संभावना से उत्पन्न होता है। इस बात की संभावना है कि प्रॉजेक्ट रिपोर्ट, जिसके आधार पर ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, अत्यधिक आशावादी है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अनुमान वास्तविकता के कितने निकट है। भले ही अनुमान को वाजिब मान लिया जाए, लेकिन इस बात की संभावना है कि बाह्य कारक अनुमान को नायाब कर सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण इससे निपटने का एक सामान्य रास्ता है। जांचा हुआ परिदृश्य पर्याप्त रूप से दबावग्रस्त एवं स्वीकार्य होना चाहिए। उन्हें उन संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो इस तथ्य पर आधारित है कि भारत पहले की अपेक्षा अधिक खुली अर्थव्यवस्था है। घरेलू प्रतिस्पर्धा के अलावा सीमापार से होने वाली प्रतिस्पर्धा को भी दृष्टि में रखना चाहिए एवं इसलिए न केवल घरेलू क्षमता बल्कि वैश्विक क्षमता भी मानदंड होना चाहिए। बैंक फोरेक्स जोखिम निहित मामलों, जिसमें विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में देयताएं शामिल हैं, को भी प्रायः कमतर आंकता है।

जैसा पहले बताया गया, संवृद्धि के दौर में हामीदारी मानकों में कमी आई, जिसे कोई तर्कहीन आधिक्य कहेगा। ऐसे मामलो में सही प्रतिसंतुलन क्या हो सकता है? प्रवर्तक का मजबूत तुलन पत्र इसका उत्तर प्रतीत होता है। फिर भी, यह प्रतीत होता है कि कॉरपोरेट लीवरेज का आकलन करने के लिए कोई पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया था। इसलिए हमारे समक्ष ऐसी स्थितियां थीं जिसमें प्रवर्तकों को बहुत ही कम नुकसान हुआ। यह क्या करता है कि कॉरपोरेट ऋणग्रस्तता की समस्या को प्रवर्तक के बजाय बैंक की समस्या बना देता है। अतः, एक दृढ़ हामीदारी व्यवस्था, जिसमें समझ एवं जोखिम-वहन क्षमता समुचित रूप से ओत-प्रोत है, ऋण जोखिम प्रबंधन का पहला तत्व है। लेकिन यह कब होगा? केवल तब जब जोखिम की संस्कृति बैंकों पर व्याप्त हो जाएगी। जोखिम संस्कृति को फैलाना बैंक बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन का कार्य है। वास्तव में बेसल समिति के अनुसार :

बैंकों के पास एक प्रभावशाली आत्मनिर्भर जोखिम प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए जो समुचित प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, स्रोत एवं बोर्ड में पहुंच रखने वाले मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के निर्देशन में कार्य करे।

जोखिम के परिदृश्य से, पोर्टफोलियो में विविधता हामीदारी का महत्वपूर्ण तत्व होगा। प्रतिपक्ष, भूगोल, आर्थिक गतिविधि और इस जैसे के अनुसार संकेंद्रण के दायरे में आने वाले ऋण पोर्टफोलियो को नुकसान पहुँचने की ज्यादा संभावना होती है। संकेंद्रण से होने वाले जोखिमों की निगरानी के लिए समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है और योजनाबद्ध तरीके से उसका समाधान किया जाना चाहिए। हमने बैंकों को 15 प्रतिशत तक की अपनी पूंजी प्रतिपक्ष पर तथा 40 प्रतिशत समूह पर निवेश (एक्सपोजर) करने की अनुमति प्रदान की है। बैंक को इन सीमाओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। 15 प्रतिशत का प्रत्येक सात एक्सपोजर बैंक की पूंजी को इन कुछ कंपनियों के प्रति अतिसंवेदनशील कर देगा। इसलिए इन सीमाओं को भिन्न प्रकार से देखने का प्रयास जारी है। यह लिंकेज न केवल स्वामित्व के जरिए बल्कि आर्थिक संबंधों के जरिए भी होगा।

प्रभावशाली संवितरण-पूर्व नियंत्रण, ऋण जोखिम प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। बैंक, जोखिम को कम करने के उपायों पर ध्यान दिए बगैर मंजूरी शर्तों में छूट प्रदान करने में काफी उदार है। करीब-करीब मंजूरी की प्रत्येक शर्त जोखिम को कम करने की क्षमता रखता है। कभी-कभी एक से अधिक, समान उद्देश्य को पूरा करते हैं। छूट दी गई आवश्यकताओं के एवज में वैकल्पिक उपायों में छूट, संशोधन एवं सुझाव का समुचित मूल्यांकन, ऋण जोखिम को कम करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।

यह कहा जाता है कि मजबूत मंजूरी-पश्च पर्यवेक्षण से खराब हामीदारी की भरपाई हो सकती है और खराब निगरानी से बखूबी मूल्य-निरूपित ऋण को हानि पहुंच सकती है। चलो मैं विस्तार से समझाता हूं। मान लो कि संयंत्र को स्थापित करने की लागत का अति आकलन किया गया और उसका तदनुसार मूल्यांकन कर दिया गया, लेकिन धन प्रवाह में सख्त नियंत्रण और मजबूत ऑन-साइट पर्यवेक्षण के जरिए जोखिम वारदात को अभी भी कम किया जा सकता है। इसके विपरीत, मंजूरी-पश्च पर्यवेक्षण में ढिलाई बरतने से प्रवर्तक समय पर

अपना अंशदान नहीं करेगा, और धन को परियोजना की लागत पर लगाए बगैर इस जैसे अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है।

दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने का तरीका जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि दबावग्रस्त आस्ति ऋण होता है जिसमें प्रत्याशित एवं या अप्रत्याशित जोखिम साफ़ दिखाई देता है। नई हामीदारी से संबंधित समस्त गतिविधियों को फिर से चालू किया जाना होगा। लेकिन क्या वह पूरा हुआ? यह चिंता का विषय है कि इस काम में कई बार दबाव की पहचान करने को टालना पड़ता है। अतः, बड़े ऋणों का पुनर्गठन चूक के लिए प्रचलित हो गया है, जिसे हमें अंततः बंद करना पड़ा। हम महसूस करते हैं कि विश्व के किसी भी भाग में कार्यशील संस्था दिवंगत संस्था से बेहतर है और दिवालियापन से निपटने की रूपरेखा की अनुपस्थिति में ऐसा हमारे देश में अधिक है। आशा करते हैं कि इसे शीघ्र ही काबू में कर लिया जाएगा क्योंकि अब इन्साल्वन्सी (ऋणशोधनक्षमता) और बैंकरप्सी (दिवालियापन) अधिनियम पारित किया जा चुका है। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैंक किसी खाते को एनपीए के रूप में क्यों नहीं वर्गीकृत कर पाता है और आवश्यकता के मुताबिक ऋण प्रदान करता आ रहा है। किसी खाते का दर्जा गिरने से रोकने के लिए की गई पुनर्गठन की व्यवस्था से बैंकों पर दबाव बढ़ता है क्योंकि इससे पहले से लाभ प्राप्त संस्था को और अधिक फ़ायदा पहुंचता है। इससे क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया से जोखिम प्रबंधन का संबंध घटता जाता है।

सैद्धांतिक तौर पर, वित्तीय जोखिम के प्रबंधन के संदर्भ में 'त्री लाइन्स ऑफ डिफेन्स मॉडल' का परंपरागत रूप से प्रयोग कॉरपोरेट गवर्नेन्स एवं बैंकों की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के बीच की परस्पर क्रिया को रूप देने के लिए किया जाता है। मैं इसे फुटबाल खेल के त्री लाइन्स ऑफ डिफेन्स की उपमा की मदद से समझाना चाहूंगा।

फुटबाल में, आगे की पंक्ति एवं मैदान के मध्य भाग के क्षेत्ररक्षकों का खेल की सफलता में अहम भूमिका होती है। यदि वे सावधानी और दृढ़ता से खेलें तो बाकी सामान्यतः सुचारू रूप से चलेगा। ऋण जोखिम प्रबंधन में, ऋण प्रदान करने वाला अधिकारी और ऋण मंजूर करने वाले प्राधिकारी फस्ट लाइन ऑफ डिफेन्स की भूमिका अदा करते हैं। परिचालनात्मक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हुए, ऋण के एक्सपोज़र में जोखिम के आकलन, नियंत्रण व रोकथाम के साथ-साथ प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके पास स्वामित्व, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है (चित्र 1)। यदि वे बैंक वित्त के प्रॉजेक्ट का चयन करते समय मूल तत्वों को छोड़ देते हैं, तो उन्हें जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षाओं पर गंभीरता से काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदत्त ऋण बैंक के लिए लाभदायक सिद्ध हो।

ऋण जोखिम प्रबंधन दूसरा लाइन ऑफ डिफेन्स है जो परिचालनात्मक प्रबंधन को प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन प्रयोगों को लागू करने में सहयोग प्रदान करता है तथा उसकी जांच करता है। फुटबाल के उदाहरण में दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स

चित्र 1: डिफेन्स मॉडल की तीन लाइनें

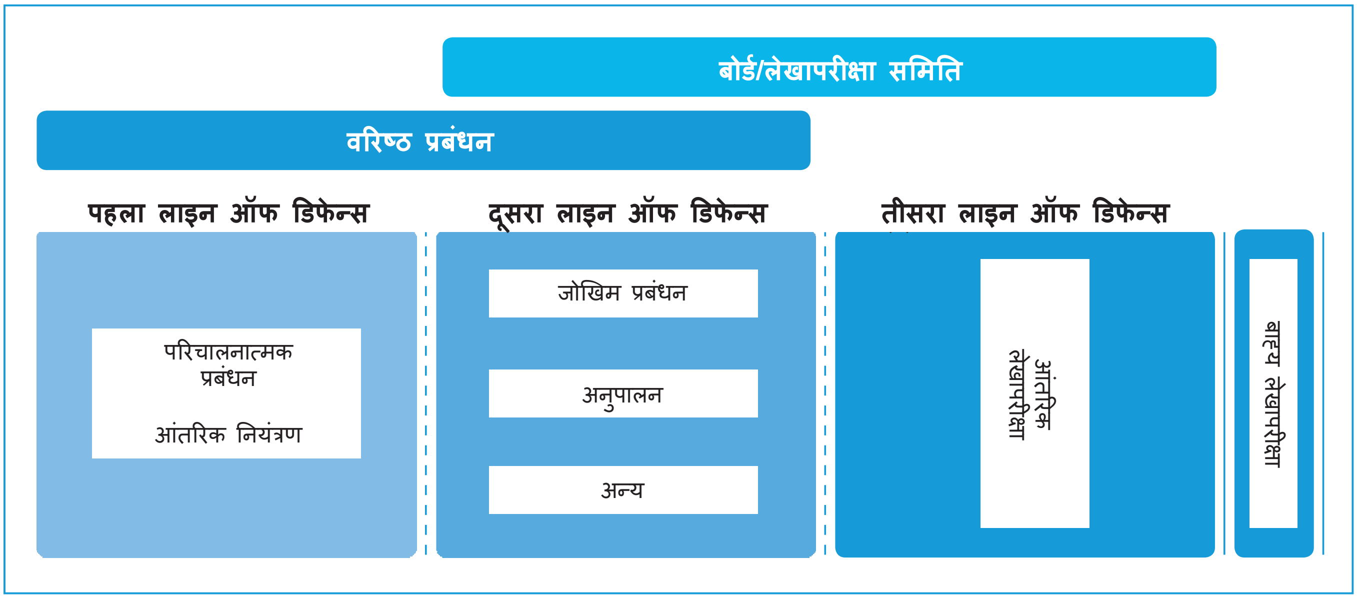

स्रोत : 8वें ईयू कंपनी नियम निदेश, अनुच्छेद 41 पर ईसीआईआईए/एफईआरएमए मार्दगर्शन।

की विभिन्न भूमिकाएं हैं। उन्हें आगे की पंक्ति के क्षेत्ररक्षकों पर नज़र रखने की जरूरत है कि वे किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं और क्या उन्हें रणनीति को बदलने के लिए आगे के क्षेत्ररक्षकों को बुलाने की जरूरत है। इसी के साथ-साथ उन्हें, यदि स्थिति आगे के क्षेत्ररक्षकों के नियंत्रण से अचानक बाहर चली जाती है तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन यह उनके लिए कदापि उचित नहीं होगा कि वे अपनी जगह छोड़ दें और आगे के क्षेत्ररक्षकों में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिद्वंदी टीम आपकी टीम पर हमला कर सकती है। इसलिए, दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स को पहले लाइन ऑफ डिफेन्स को केवल मजबूती प्रदान करनी चाहिए न कि उनकी जगह लेनी चाहिए। ऋण जोखिम प्रबंधन में, दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स को जोखिम के मालिकों अर्थात् ऋण विभाग को लक्षित जोखिम एक्सपोजर को परिभाषित करने तथा संगठन के जरिए जोखिम संबंधी पर्याप्त जानकारी की सूचना देने में सहयोग करना चाहिए। यदि इस लाइन ऑफ डिफेन्स को कारगर तरीके से कार्य करना है तो उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा। जोखिम प्रबंधन अधिकारी ऋण अनुमोदन समितियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

आंतरिक लेखा परीक्षा तीसरा लाइन ऑफ डिफेन्स है और यह संगठन के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को आश्वासन प्रदान करता है कि संगठन अपने जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने में कितना कारगर है। यह विशेष रूप से पहले और दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स के कार्य करने के तरीके पर नज़र रखता है। आश्वासन की भूमिका संस्था की जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के सभी तत्वों अर्थात् जोखिम की पहचान करना, जोखिम का आकलन करना और जोखिम संबंधी जानकारी के संप्रेषण की प्रतिक्रिया को पूरा करता है। इसे फुटबाल के खेल के साथ तुलना करें तो कोई यह अपेक्षा नहीं करेगा कि गोलकीपर आगे की पंक्ति के क्षेत्ररक्षकों के साथ दौड़ते हुए मैदान के मध्य भाग को छोड़ आगे जाकर गोल दागे। साथ ही, कोई टीम खेल में जीत के लिए केवल एक मजबूत गोलकीपर पर सदैव निर्भर नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, कोई आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम प्रबंधन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, जो प्राथमिक तौर पर परिचालनात्मक, जोखिम प्रबंधन एवं अनुपालन दलों का उत्तरदायित्व है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ऋण जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा विभागों की संगठनात्मक एवं रिपोर्टिंग संरचना के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किया है। यदि सभी संस्थागत प्रक्रियाओं को काम में लाना है, तो उन्हें अनुपालन हेतु निर्धारित बक्से में मात्र निशान के बजाय अपेक्षित भूमिका अदा करने के लिए अवश्य तैयार करना चाहिए।

निम्नांकित स्थितियों में लाइन ऑफ डिफेन्स के विभिन्न मॉडल कारगर सिद्ध नहीं होंगे :

- पहले लाइन ऑफ डिफेन्स में जोखिम उठाने वालों को असमान प्रोत्साहन, जो मुख्य रूप से संस्था के लिए पर्याप्त राजस्व और लाभ अर्जित करने पर बल देने की वजह से होता है।
- दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स में संगठनात्मक स्वतंत्रता की कमी।
- दूसरे लाइन ऑफ डिफेन्स में दक्षता और विद्वता की कमी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जोखिम का अपर्याप्त एवं विषयपरक आकलन।

अब मैं, तीनों लाइन ऑफ डिफेन्स के साथ-साथ बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा पूरा करता हूं। आखिरकार खेल का एक बड़ा हिस्सा रणनीति बनाने और परामर्श देने से जीता जाता है। खिलाड़ियों के पास अमल करने योग्य योजना होनी चाहिए जो प्रतिद्वंदी की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन कर बनाई गई हो। बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन बैंक की जोखिम रणनीति बनाता है, संगठन के लिए जोखिम-वहन क्षमता निर्धारित करता है तथा प्रत्येक खिलाड़ी एवं खिलाड़ी समूह को उनकी भूमिकाएं सौंपता है। इस प्रकार वे टीम के कोच और प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान दें, यदि आप किसी लोकप्रिय फुटबाल लीग को देखें तो पता चलेगा कि कोच और प्रबंधक, टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।

परिणाम

यदि बैंक लंबे समय तक भारी एनपीए की समस्या से जूझता रहेगा तो इससे बैंक जोखिम विमुख हो जाएगा और इस प्रकार सामान्य रूप में आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता में रुकावट आएगी। दूसरा परिणाम यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का व्यक्तिगत ऋण और आवास ऋणों जैसे ऋण वर्गों में एक्सपोजर की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि इन ऋण वर्गों में बैंकों का एनपीए अब तक सबसे कम रहा है। इससे कम अस्थिरता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के जरिए ऋण पोर्टफोलियो में पुनः संतुलन बनाने में मदद हो सकती है, लेकिन ध्यान देना होगा कि इसमें अति न होने पाए और इस प्रकार लाभ को कॉरपोरेट क्षेत्र से हाउसहोल्ड क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। दूसरी संभावना यह भी है कि औद्योगिक ऋणों में निजी क्षेत्र के बैंकों का बाजार में हिस्सा बढ़े। यह पहले ही होता दिखाई दे रहा है। इससे व्यवहार्य कारोबार को बैंक वित्त का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो बैंकिंग क्षेत्र अभी भी दबाव में है। फिर भी, बैंकों को परिणामी ऋण संकेंद्रण जोखिम के लिए उचित उपाय

करने होंगे। समग्र रूप से देखें तो, दबावग्रस्त आस्तियों से दृढ़तापूर्वक निपटना देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक उपाय किए गए।

सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए गए साधन

सरकार द्वारा किए गए उपाय

ऋणों में चूक के परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान, खराब वसूली की वजह से और अधिक हो जाता है। विशेष रूप से, कानून की मदद से अत्यधिक कम मात्रा में वसूली करना चिंता का कारण है। सरफेसी अधिनियम, डीआरटी एवं लोक अदालतों के तहत दायर मामलों की संख्या के प्रतिशत के रूप में वार्षिक वसूली 2013-14 के 20 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 9 प्रतिशत रह गई है। सरकार ने डीआरटी और सरफेसी अधिनियम में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिससे हम वसूली प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद करते हैं। इन्साल्वन्सी और बैंकरप्सी कोड सरकार द्वारा इस दिशा में लिया गया एक और बड़ा कदम है। सरकार ने इस कोड को कम समयावधि में चालू करने के लिए विस्तृत विनियम और नियम निरूपित करने हेतु एक समिति गठित की है, जिसमें चार उप-समूह शामिल हैं।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेन्स को बेहतर करने के भी उपाय किए हैं। इंद्रधनुष पहल बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के बेहतर कार्यनिष्पादन में सहयोग करेगा, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को विभाजित करना, बैंक बोर्ड ब्यूरो के जरिए बोर्ड और प्रबंधन की नियुक्तियों में दृढ़ता लाना एवं विकेन्द्रीकरण के जरिए अधिकतर निर्णय का अधिकार पेशेवर बोर्ड को सौंपना तथा प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करना शामिल हैं। सरकार ने बैंकों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी लगाई है।

विनियामक उपाय

बैंकों की अनर्जक आस्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि ने भारतीय रिज़र्व बैंक का भी विशेष ध्यान आकर्षित किया है। 2014 की शुरूआत में दबावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए तैयार की गई रूपरेखा से लेकर, हमने इनसे निपटने के लिए बैंकों को सशक्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। यह जानते हुए कि ऋण के सही मूल्यांकन और ऋण की सुदृढ़ निगरानी के संबंध में सूचना में एकरूपता न होना एक बड़ी समस्या है, आरबीआई ने उन बड़े ऋणों (सीआरआईएलसी) का डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक के सभी ऋण शामिल हैं। सभी बैंक इस डेटाबेस का एक्सेस कर सकते हैं। इस डेटाबेस के जरिए बैंकों को प्रारंभिक रुग्णता का पता चलता है जो ऋण अदायगी के व्यवहार से प्रतिबिंबित होता है। उधारदाता, सीआरआईएलसी डेटाबेस का लाभ उठाते हुए, संयुक्त उधारदाता फोरम (जेएलएफ) के माध्यम से रुग्णता के प्रारंभिक संकेत के दिखाई देते ही प्रभावित इकाई की वसूली और समाधान के लिए एक साथ मिलकर योजना बना सकते हैं। त्वरित निर्णय लेने के लिए बैंकों को प्रत्सोहित किया जा चुका है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि फोरम प्रभावशाली तरीके से कार्य कर रहा है।

आरबीआई के विनियमों के मुताबिक बैंकों को ऋणों को बीते दिनों पर आधारित विशेष रूप से उल्लेख की गई श्रेणियों में वर्गीकृत करने की जरूरत है, ताकि उसकी बेहतर निगरानी की जा सके। दरअसल ऋणों का पुनर्गठन कोई बुरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने बैंकों के अलाभकारी परियोजनाओं के पुनर्गठन को करीब-करीब समाप्त कर दिया है और उसे मानक आस्तियों के रूप में भी वर्गीकृत किया हुआ है। उसके साथ-साथ, उधारकर्ता को दीर्घावधि परियोजना के लिए ऋण की अदायगी के लिए उनके चुकौती कार्यक्रम और नकदी प्रवाह के बीच बेहतर तालमेल का लाभ प्राप्त होने के उद्देश्य से 5/25 योजना तैयार की गई है। हम योजना के कार्यनिष्पादन की लगातर जांच और जहां कहीं जरूरी लगे उसमें सुधार करते आ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर ऋणों को सदा अच्छा बनाए रखने के लिए उसका गलत उपयोग तो नहीं किया जा रहा है तथा छोटी-मोटी समस्या यदि कोई हो का समाधान किया जा सके।

एसडीआर योजना उन समस्यामूलक ऋणों से निपटने के लिए तैयार की गई है, जहां प्रवर्तकों को बदले जाने की जरूरत है, जबकि 'दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना की योजना' (एस4ए) बड़े दबावग्रस्त खातों के समाधान की वैकल्पिक रूपरेखा है जहां प्रवर्तकों को बदलने की जरूरत नहीं है। एस4ए दबावग्रस्त उधारकर्ता का धारणीय ऋण स्तर निर्धारित करता है और बकाया ऋण को धारणीय ऋण और इक्विटी/ अर्ध-इक्विटी लिखतों में विभाजित करता है और इससे यह अपेक्षा की जाती है कि यदि उधारकर्ता ऋण चुका नहीं पाता है तो उक्त निवेश के मूल्य में वृद्धि से ऋणदाता को लाभ पहुंच सकता है। यह कार्य के निष्पादन के लिए काबिल और अत्यधिक लाभ प्राप्त प्रवर्तकों को तथा उधार देने के सिलसिले को, प्रॉजेक्ट को एनपीए नहीं माने जाने के कारण, जारी रखने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।

भारत के बैंक बेसल III और संशोधित आईएफआरएस को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से पहले दबाव में आ गए थे, जिसे प्रणाली स्तर के दबावों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। विशेष रूप से, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

और अपेक्षित हानि आधारित प्रावधानों से बैंकों में दृढ़ता आएगी और इस प्रकार प्रणालीगत जोखिम की वारदातों से बचने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनेगी। बेसल III के सभी समष्टि विवेकपूर्ण एवं प्रतिचक्रीय तत्वों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे सभी बैंकों को अच्छे समय में पूंजी की बचत के लिए बढ़ावा मिलता है ताकि बुरे समय में उसका उपयोग किया जा सके। भारतीय बैंकों के मामले में, दबाव की स्थिति बेसल III को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से पहले ही आ चुकी थी और वह भी इस हद तक कि इस संशोधित पूंजी मानक का लाभ उन्हें प्राप्त न हो सका। इसके अलावा, बेसल III को इस दबावग्रस्त चरण में लागू किए जाने की वजह से भारतीय बैंकों पर दबाव दुगुना हो गया है, क्योंकि उन्हें वर्तमान दबाव का सामना करने के साथ-साथ बेसल III को लागू भी करना है। अतः, बाह्य पूंजी सहायता अनिवार्य है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक पूंजी सहायता पहले ही उपलब्ध करा दी है, यद्यपि इसमें कार्य निष्पादन के संबंध में कतिपय शर्तें भी शामिल हैं। इंद्रधनुष के हिस्से के रूप में और पूंजी लगाई जाएगी। लेकिन यह आवश्यक है कि बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों को काबू में किया जाए और बैंक पर्याप्त आंतरिक उपचय फिर से कर सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही दबाव की स्थिति दूर हो जाएगी, बैंक और मजबूत होगा।

अपराध

रिज़र्व बैंक मानता है कि कारोबार में आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं और कारोबार की वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन अपराध के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए, हमने जानबूझकर चूक करने वालों एवं असहयोगी उधारकर्ताओं का पता लगाने के लिए विस्तृत व्यवस्था कर रखी है और इस प्रकार घोषित उधारकर्ताओं को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम यह भी मानते हैं कि धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसलिए हमने धोखाधड़ी रजिस्ट्री बनाई है।

परियोजना के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना

उत्तरी अमरीका को छोड़कर, बैंक ऋण, परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रमुख स्रोत बना रहा। इस प्रकार के दीर्घकालिक वित्तपोषण से बैंक के तुलन पत्रों में पैदा होने वाले पर्याप्त जोखिमों को जानते हुए, परियोजना के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार से धन उठाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है और इसे होशहवास में कई अन्य देशों में बढ़ावा दिया जा रहा है।

मिसाल के तौर पर, यूरोप में, बांड के जरिए परियोजनाओं का वित्तपोषण 2008 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 23 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 11)। हमने दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें बड़े उधारकर्ताओं को अपनी आंशिक धन संबंधी जरूरतों के लिए पूंजी बाजार का सहारा लेने को कहा गया है। बड़े एक्सपोज़र के संबंध में संशोधित प्रारूप जारी किया जा चुका है। हमने, बांड जारी करने के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि की है ताकि उसे दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके।

चार्ट 11: यूरोप में बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रवृत्ति

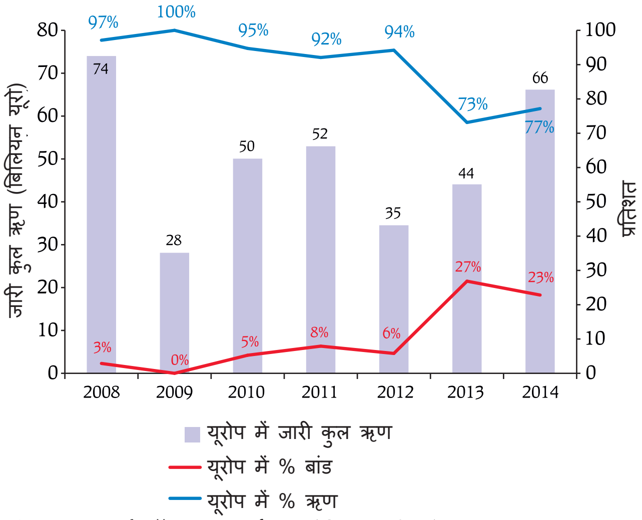

स्रोत : पीएफआई थॉमसन रायटर्स, फाइनेन्शियल लीग टेबल्स।

निष्कर्ष

जिस बैंक का जोखिम प्रबंधन मज़बूत नहीं होता, उसका ऋण पोर्टफोलियो अत्यधिक संवेदनशील होने की संभावना है। जोखिम प्रबंधन स्थिर नहीं होता। वह समय के साथ-साथ विकसित होता है। यह जरूरी नहीं है कि वह सबके लिए एक जैसा हो। बैंक की कार्य पद्धति में जटिलताओं के बढ़ने के साथ-साथ उसकी कृत्रिमता बढ़ती है। वास्तव में, यदि बैंक का जोखिम प्रबंधन उसके कार्यों की जटिलताओं के मुताबिक नहीं है, तो इससे उसको जोखिम होने का खतरा है और वह उसकी जोखिम-वहन क्षमता के काबू से बाहर जा सकता है। विनियामकों ने जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की है। यह बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के हाथ में है कि किस प्रकार उसको सही रूप में काम में लाया जा सके और किस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न लाइन्स ऑफ डिफेन्स अपनी-अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। बैंक में मजबूत जोखिम प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्ध बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन से बढ़कर कोई लाइन ऑफ डिफेन्स नहीं है।

धन्यवाद।